

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 337/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/494

अनवान

1. श्री दल्लू पिता चतुरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री घोरा पिता चतुरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
3. श्री बालू पिता चतुरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
4. श्री रामा पिता माना रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
5. श्री लोना पिता माना रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
6. श्रीमती भमरीबाई पत्नि शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
7. श्री लक्ष्मण पिता शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
8. सुश्री गुडडी पुत्री शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
9. श्री नानालाल पिता शंकर रावत जरिये नाबालिग बविलायत माता श्रीमती भमरीबाई पत्नि शंकर जी रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अमरा पिता गौतम रावत निवासी आकोला कुण्डिया वेला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री लोमर पिता गौतम रावत निवासी आकोला कुण्डिया वेला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: : निर्णय :-

दिनांक 02.09.2024

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी नम्बर 1605, 1607 कुल कित्ता 2 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा भूमि स्थित हैं जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम पर अंकित हैं। वादीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1979 को श्री भग्ना पिता उदा जी रावत व श्री आला पिता उदा जी रावत निवासी आकोला फला कुण्डीवेली तहसील वल्लभनगर ने वादीगण के पूर्वाधिकार चतुरा माना पिता सदा जी रावत निवासी देवरी को आराजी न. 1605 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा भूमि वि. रूपया 700/- के प्रतिफल में विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया एवं दिनांक 30.01.1979 को ही श्री रामा पिता नवला जी रावत निवासी आकोला फला - कुण्डीवेली तहसील वल्लभनगर

ने अपनी आराजी 1607 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा भूमि को हमारे पूर्वाधिकारी कतरा माना पिता सवा ली रावत निवासी देवरी को दित एवज रूपया 1500/- के प्रतिफल में विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया तब से उक्त भूमि पर हमारे पूजा एव उनके मृत्युपरान्त वादीगणों को कब्जा काश्त निरन्तर निराबाध रूप से चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह धमकी दी कि उक्त आराजीयात का कब्जा हटा ली वरना हम जवरन उक्त भूमि पर काबिज हो जायेंगे एव तुमको बदखल कर देंगे इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी का जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश नहीं कर वादपत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया तथा अनुपरिथत रहने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी डब्लु-1 चौखा पुत्र चतरा, पी डब्लु-2 लोगर पुत्र माना के पेश किये गये तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत् 2051-54 प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 कराई गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा वहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी वहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र जवाब पेश नहीं किया गया है। हमने पाया की वादग्रस्त आराजीयात वादी संख्या 1 से 5 व वादी संख्या 6 से 9 के पिता/पति के नाम दर्ज हैं जो जमाबंदी संवत् 2051-54 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 से स्पष्ट हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं जिससे प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में दखलअंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता है। प्रकरण में वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं जिससे प्रतिवादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

— : आदेश : —

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2051-54 की आराजी नम्बर 1605, 1607 कुल कित्ता 2 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के वाद बन नये नम्बरान के आधार पर प्रतिवादीगण जवरन कब्जा नहीं करें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। डिक्री पूर्वा जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।